

मेहिंदर सिंह सुलार के सामने, नयायाधीश

आयकर अधिकारी और अन्य — याचिकाकर्ता

बनाम

सुदेश शर्मा — उत्तरदाता

2014 का सी र म नम्बर म आ २०१४ का

10 नवंबर 2014

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 — अनुच्छेद 378 और 468 — भारतीय दंड संहिता, 1860 — अनुच्छेद 177 और 182 — सीमा अधिनियम, 1963 — अनुच्छेद 5 — बरी होने के खिलाफ अपील का दायरा — संज्ञान — सीमा — अपीलकर्ता ने प्रतिवादी के खिलाफ शिकायत दर्ज की जिसमें आरोप लगाया गया कि आँकलन करने वाले ने उसके माध्यम से प्रस्तुत गलत टीडीएस प्रमाणपत्रों के आधार पर धनवापसी का दावा किया है — शिकायत को गधे के खिलाफ स्थापित नहीं किया गया है — केवल एक प्रतिवादी जो आरोपी के रूप में आँकलन करने वाले के वकील थे- कर रिटर्न मूल्यांकन वर्ष 1987-88 के लिए प्रस्तुत किया गया — समन आदेश पारित हुआ 3.7.1999 — ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए गए उत्तरदाता — बरी होने के फैसला के खिलाफ अपील — आयोजित किया गया है कि, आँकलन करने वाले ने धनवापसी का दावा किया था जाली टीडीएस प्रमाण पत्र के आधार पर — उत्तरदाता जो एक वकील था ने केवल आयकर रिटर्न जमा किया था आँकलन करने वाले की ओर से- उसे नहीं आरोपी ठहराया जा सकता खरीदे गए दस्तावेजों के अपराधिक अभियोजन के लिए जो कि आँकलन करने वाले व्यक्ति द्वारा खरीदे गए थे — आगे आयोजित, अधिकतम सजा जो की निर्धारित की गयी है संकेतित धाराओं के तहत वह 6 महीने तक बढ़ सकती है — धारा 468 यह बताता है कि कोई भी अदालत इस तरह के अपराधों की एक वर्ष की अवधि समाप्ति के बाद संज्ञान नहीं लेगी — वह उद्देश्य जिसे कानून आगे बढ़ना चाहता है वह स्पष्ट रूप से अनुरूप है निष्पक्षता और त्वरित सुनवाई की अवधारणा से जो की भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में अवतरित है — अनिवार्य और वैधानिक रोक जो की धारा 468 दंड प्रक्रिया संहिता द्वारा बनाई गई उसे किसी भी परिस्थिति में टालना नहीं हो सकता है और नहीं होना चाहिए — अनुभूति साथ ही सीमा से वर्जित - आगे आयोजित किया गया, कि बरी होने के निर्णय जो की वैध करणों के साथ हैं उन्मे सीमित क्षेत्राधिकार के प्रयोग जो की धारा 378 (4) सी आर पी सी के तहत किया जाता है, उसके कारण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अवैध, विकृत न हों और अधिकार क्षेत्र के बिना ना हो।

आयोजित किया गया की, प्रतिवादी-अभियुक्त ने केवल आँकलन करने वाले की ओर से सभी इंगित दस्तावेजों के साथ आयकर रिटर्न मुख्य प्रस्तुत किया था। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो, सभी टीडीएस प्रमाण पत्र, जो उत्तरी रेलवे द्वारा जारी किए गए, वह आँकलन करने वाले के द्वारा अधिवक्ता को दिए गए थे। यह मुख्य आँकलन करने वाले थे, जो संबंधित अधिकारियों से दस्तावेज खरीदे थे और धनवापसी का दावा किया। मामले में, मुख्य आँकलन करने वाले ने धनवापसी का दावा किया था

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

जाली टीडीएस प्रमाणपत्रों के आधार पर, फिर, आयकर अधिकारी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत अच्छी तरह से आयकर के वापसी को अस्वीकार करने के लिए उनके अधिकार क्षेत्र में सक्षम थे। इसके बाद, पीड़ित पक्ष को प्रासंगिक संबंध के तहत अपील दायर करने का अधिकार था। इस में, जैसा कि हो सकता है, वैसा ही हो घटना, प्रतिवादी-आरोपी, जो एक वकील था, बस मुख्य आँकलन करने वाले की ओर से आयकर रिटर्न जमा करने आया था और इसी कारण संभवतः और वास्तव में आपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है मुख्य आँकलन करने वाले द्वारा दस्तावेजों की खरीद के लिए संकेतित अपराधों के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, जैसा कि इसके विपरीत शिकायतकर्ता आईटीओ ने कहा है। इसी तरह, केवल तथ्य यह है कि उसने आँकलन करने वाले की ओर से आयकर रिटर्न तैयार किया था, वास्तव में, यह एक आधार नहीं है और इतना ठोस सबूत नहीं है कि प्रतिवादी-अभियुक्त को धारा 177 और 182 आईपीसी के तहत आँकलन करने वाले की अनुपस्थिति में दोषी करार करने के लिए।

(उपधारा 14)

आगे आयोजित, इतना ही नहीं, इस मामले का एक और पहलू है, जिसे पूरी तरह से एक अलग कोण से देखा जा सकता है। रिकॉर्ड के अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने 24-11-1989 को आयकर रिटर्न जमा किया था और मुख्य आँकलन करने वाले ने रेलवे अधिकारियों से बहुत पहले टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। प्रतिवादी अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था, 3-7-1999 दिनांकित समन आदेश द्वारा और अंततः उसे धारा 177 और 182 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए चरगेशीत किया गया था। संभवतः यहाँ विवादित नहीं हो सकता है संकेतित अपराधों के तहत निर्धारित अधिकतम सज़ा सरल है जिसकी कारावास की अवधि, जो प्रत्येक या छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना है, जो रु 1000 / - प्रत्येक या दोनों के साथ विस्तारित हो सकता है। क्रमानुसार, धारा 468 सी.आर.पी.सी. यह बताती है कि कोई भी न्यायालय अपराध का एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान नहीं लेगा जैसा की धारा 468 (1) (2) (बी) सी.आर.पी.सी.में लिखा है। धारा 468 सी.आर.पी.सी. का कार्यवाही की सीमा को रोकने के पीछे उद्देश्य यह है कि पार्टियाँ लंबे समय (देरी) के बाद मामले दर्ज करने ना आए और अपराध की तारीख के बाद लंबे समय के बाद झूठे और बेबुनियादि मामले दायर करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए। यह उद्देश्य जिसे क़ानून आगे बढ़ना चाहता है वह स्पष्ट रूप से अनुरूप है निष्पक्षता और त्वरित सुनवाई की अवधारणा से जो की भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 मे अवतरित है। इस प्रकार, यह अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अभियोजन राज्य द्वारा या निजी शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया हमेशा स्थापित कानून का पालन करने वाला होना चाहिए या फिर अभियोजन सीमा का आधार पर विफल होने के जोखिम को उठाए। मेरे दिमाग के अनुसार, धारा 468 सी.आर.पी.सी. द्वारा लगाए अनिवार्य और वैधानिक बार को किसी भी परिस्थिति में और वास्तव में अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से, क्या बात करनी है मुख्य आँकलन करने वाले की अनुपस्थिति में, प्रतिवादी अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए, यहां तक कि उसके खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत कानून की नजर में गैर है।

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

(उपधारा 15)

आगे आयोजित, कि इंगित अपराधों का प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लेना सीमा द्वारा भी रोक दिया गया था। वैध कारणों से बरी होने के ऐसे स्पष्ट रूप से लगाए गए निर्णय, जो की वैध कारणों के साथ हैं उन्मे सीमित क्षेत्राधिकार के प्रयोग जो की धारा 378 (4) सी आर पी सी के तहत किया जाता है, उसके कारण से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता जब तक कि वह अवैध, विकृत न हों और अधिकार क्षेत्र के बिना ना हो। चूंकि ऐसा कोई स्पष्ट अवैधता या कानूनी दुर्बलता को याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा इंगित नहीं किया गया है, इसलिए, बरी होने के लिए लगाए गए निर्णय योग्य हैं और यहां दिए गए कारणों और मामले की प्राप्त परिस्थितियों के लिए बनाए रखा गया है।

(उपधारा 16 और 17)

योगेश पुटनी, याचिकाकर्ता के लिए अधिवक्ता

मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश

- (1) कानून और तथ्यों के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए, मैं अपील करने के लिए छुट्टी के संकेतित याचिकाओं जो की एक ही तिथि के समान लगाए गए निर्णयों से एक ही पार्टियों के बीच उत्पन्न हुए हैं, के निपटान का प्रस्ताव इस सामान्य आदेश द्वारा दोहराव से बचने के लिए करता हूं। हालांकि, तथ्यों की साजिश जो वर्तमान याचिकाओं में शामिल है, जिसके उल्लेख की मुख्य विवाद को तय करने के लिए आवश्यकता है, को निकाला गया है।
- (2) तथ्यों और साक्ष्यों का मैट्रिक्स के दौरान परीक्षण का पाठ्यक्रम सामने आया, प्रारंभ में समापन, प्रासंगिक अपील की छुट्टी की तत्काल याचिकाएं का प्रासंगिक अपील की छुट्टी की तत्काल याचिकाएं का निर्णय लेने के लिए और रिकॉर्ड से यह सामना आया है कि शुरू में, मुख्य आँकलन करने वाले अशोक कुमार शर्मा भगवान दस के बेटे, रेल्वे ठेकेदार ने सुदेश शर्मा, प्रतिवादी-अभियुक्त को काम पर लगाया और उसे मूल्यांकन वर्ष 1987-88 का आयकर रिटर्न प्रस्तुत करने के उद्देश्य से अपेक्षित दस्तावेज और टीडीएस प्रमाण पत्र दिए। नतीजतन, प्रतिवादी ने मुख्य आँकलन करने वाले की ओर से आयकर रिटर्न भरा था 3395 / - की वापसी का दावा किया वरिष्ठ मंडल लेखा अधिकारी, उत्तरी रेलवे, नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए टी दी एस प्रमाण पत्र के आधार पर। शिकायतकर्ता - आयकर अधिकारी के मद्देनजर सत्यापन ने कहा की टीडीएस प्रमाणपत्र वास्तविक नहीं पाए गए और मुख्य गधे आँकलन करने वाले द्वारा धनवापसी का गलत दावा किया गया।
- (3) विभिन्न प्रकार के आरोपों को समतल करना और अनुक्रम से विस्तार से घटनाओं का वर्णन करना, शिकायतकर्ता के अनुसार, मुख्य आँकलन करने वाले ने गलत टी दी एस प्रमाण पत्र के आधार पर 3395/- के धनवापसी का गलत दावा किया है प्रतिवादी -आरोपी सुदेश कुमार अधिवक्ता के माध्यम से। इन आरोपों की पृष्ठभूमि में, शिकायतकर्ता आईटीओ ने विभिन्न शिकायतों की स्थापना की थी, मुख्य आँकलन करने वाले के खिलाफ नहीं, बल्कि सुदेश शर्मा एडवोकेट के खिलाफ, यहाँ ऊपर दर्शाया गया तरीका के अनुसार। इसी तरह की शिकायतें भी दर्ज की गईं शिकायतकर्ता-आईटीओ द्वारा प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ अन्य जुड़े मामलों में मुख्य आँकलन करने वालों के विरुद्ध।

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

- (4) सभी कोडल औपचारिकताओं के पूरा होने के बाद, अंततः प्रतिवादी-अभियुक्त को बुलाने का आदेश दिया गया था, ट्रायल कोर्ट द्वारा समन आदेश दिनांक 3.7.1999 के आधार पर। नतीजतन, वह आईपीसी की धारा 177 और 182 के तहत अपराध करने के लिए चरगोशीत किया गया। चार्ज शीट के शब्दों को पढ़ा गया और प्रतिवादी को समझाया गया, जिसके लिए, उसने दोषी नहीं होने का अनुरोध किया और परीक्षण का दावा किया। इसके बाद, शिकायतकर्ता द्वारा सबूत के लिए परीक्षणकोर्ट द्वारा मामले को तय किया गया।
- (5) शिकायतकर्ता के साक्ष्य को बंद करने के बाद, प्रतिवादी-अभियुक्त के धारा 313 के तहत बयान दर्ज किए गए। उसे सक्षम रूप से किसी भी परिस्थिति की व्याख्या करने के लिए पूरे घटते सबूत जो की उसके खिलाफ रिकॉर्ड में थे, वह सारे उसके सामने रखे गए थे। तथापि, उन्होंने अपनी समग्रता में शिकायतकर्ता के साक्ष्य का खंडन किया था और उसके द्वारा शिकायतकर्ता आईटीओ के खिलाफ सिविल सूट दाखिल करने के कारण झूठे निहितार्थ का अनुरोध किया। अपने बचाव के समर्थन में, उन्होंने जांच की DW1 के रूप में राम धन बब्बर की और अपने रक्षा साक्ष्य को बंद कर दिया।
- (6) इसी तरह, रिकॉर्ड पर तथ्यों और सबूतों की समग्रता को ध्यान में रखते हुए, प्रतिवादी-आरोपी को ट्रायल कोर्ट द्वारा 8.5.2012 को किए गए फैसले के माध्यम से बरी कर दिया गया।
- (7) इस प्रकार, शिकायतकर्ता आईटीओ द्वारा दायर अपील अपीलीय न्यायालय द्वारा दिनांक 19.9.2013 (अनुलग्नक ए 4) के निर्णयों के आधार पर, अनुरक्षणीय ना होने के कारण को खारिज कर दिया गया था
- (8) क्रमानुसार, शिकायतकर्ता-आइ टी ओ अभी भी संतुष्ट महसूस नहीं किया और बरी करने के लिए लगाए गए इन नतीजों के खिलाफ अपील करने के लिए छुट्टी की तत्काल समय वर्जित याचिकाएं दायर करी, 378 (4) सी आर पी सी के अनुभाग के प्रावधानों को लागू किया साथ-साथ सीमा अधिनियम के आवेदन धारा 5 के दवरा 547 दिनों की देरी (मुख्य मामले में) को माफ करने की माँग की, जो निश्चित रूप से पहले से ही अलग-अलग तारीख के आदेशों के माध्यम से माफ़ कर दी गयी है। इस तरह मुझे मामले को जब्त कर लिया गया है।
- (9) याचिकाकर्ता के वकील को सुनने के बाद, रिकॉर्ड को उनकी बहुमूल्य मदद के साथ पढ़ने के बाद और पूरे मामले पर विचारों के इनायत के बाद, मेरे अनुसार, इस मामले में कोई योग्यता नहीं है और अपील के लिए छुट्टी के संबंध में दी गयी वर्तमान याचिकाएं इसमें खारिज होने के लायक हैं।
- (10) अधिवक्ता के कहना था कि रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत थे, इसलिए, ट्रायल कोर्ट ने एक कानूनी अपराध किया है प्रतिसाद के माध्यम से प्रतिवादी-अभियुक्त को बरी करके, यह बात न केवल योग्यता से रहित है, बल्कि गलत भी है।
- (11) शुरुआत से देखते हुए, यह यहाँ कहा जा सकता है कि बरी होने के मामले में अपीलीय न्यायालय का अधिकार क्षेत्र का निर्धारण माननीय एपेक्स कोर्ट द्वारा किया गया था के एक प्रसिद्ध फैसले में **घुरी लाल बनाम राज्य का यूपी!** धारा 378, 386 सी आर पी सी और इस बात पर अन्य निर्णयों, इसके तहत निर्धारित किया गया था (उपधारा 75):-

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

75. उपरोक्त के प्रकाश में, उच्च न्यायालय और अन्य अपीलीय अदालतों को अच्छी तरह से नतीजों में तय किए गए सिद्धांतों का पालन करना चाहिए यदि यह ट्रायल कोर्ट के निर्णय को रद्द करते हैं या बदलते हैं

1. अपीलीय अदालत केवल तब रद्द करेगी या अन्यथा छेड़ छाड़ करेगी ट्रायल कोर्ट के बरी होने निर्णय को यदि उसके पास "बहुत पर्याप्त और सम्मोहक कारण है" ऐसा करने के लिए।

ऐसे कई उदाहरण सामने आते हैं जिनमें अपीलीय अदालत के पास "बहुत पर्याप्त और सम्मोहक कारण" होंगे ट्रायल कोर्ट के फैसले को छोड़ने के लिए। "बहुत पर्याप्त और सम्मोहक कारण" जब मौजूद होते हैं:

- i) तथ्यों के संबंध में ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष स्पष्ट रूप से गलत है;
- ii) ट्रायल कोर्ट का फैसला कानून के एक गलत दृष्टिकोण पर आधारित था;
- iii) ट्रायल कोर्ट के फैसले के परिणामस्वरूप न्याय का गंभीर क़त्ल होने की संभावना है";
- iv) सबूत से निपटने का ट्रायल कोर्ट का पूरा दृष्टिकोण अवैध था;
- v) ट्रायल कोर्ट का फैसला स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण था और अनुचित था;
- vi) ट्रायल कोर्ट ने सबूतों को अनदेखा किया या गलत रूप से पढ़ा या ज़रूरी दस्तावेजों जैसे मरने की घोषणा / बैलिस्टिक विशेषज्ञ की रिपोर्ट, आदि को अनदेखा किया;
- vii) इस सूची का उद्देश्य चित्रण है, संपूर्ण नहीं।

2. अपीलीय न्यायालय को ट्रायल कोर्ट के निष्कर्षों और विचार पर हमेशा उचित वजन देना चाहिए।

3. यदि दो उचित विचारों तक पहुँचा जा सकता है - एक जो बरी की ओर जाता है और दूसरा सज़ा की ओर - उच्च न्यायालय / अपीलीय न्यायालय को हमेशा आरोपी के पक्ष में निर्णय लेना चाहिए।

(12) इस प्रकार कानूनी स्थिति का होना और रिकॉर्ड पर सबूत का होना, अब एक छोटा और महत्वपूर्ण प्रश्न, हालांकि महत्वपूर्ण है, जो की इस न्यायालय का तत्काल ध्यान और तत्काल याचिकाएं में विचार आमंत्रित करता है, कि क्या ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी-अभियुक्त को बरी करने के लिए इस तरह की न्यायिक त्रुटि या पेटेंट अवैधता की है और क्या पर्याप्त और सम्मोहक कारण हैं इस न्यायालय के द्वारा बरी किए गए निर्णय को पलटने के लिए या नहीं ?

(13) याचिकाकर्ता के वकील के तर्क को मद्देनज़र रखते हुए, मेरे लिए, उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक में होना चाहिए, जैसा कि शिकायतकर्ता-आईटीओ इस प्रासंगिक संबंध में बुरी तरह से विफल रहा है और यह वर्तमान याचिकाएं अपील के लिए छुट्टी के लिए खारिज करने के लायक हैं यहाँ नीचे वर्णित कारणों की वजह से।

(14) जैसा कि रिकॉर्ड से स्पष्ट है कि शिकायतकर्ता-आईटीओ दावा किया है कि मुख्य ऑकलन करने वाले ने आयकर रिटर्न जमा किया है मूल्यांकन वर्ष 1987-88 का और गलत टीडीएस प्रमाण पत्र के आधार पर रुपए 3395 / - धनवापसी का दावा करता है प्रतिवादी-अभियुक्त सुदेश

शर्मा, अधिवक्ता के माध्यम से। काफी अजीब, है की शिकायतकर्ता आईटीओ ने मुख्य आँकलन करने वालेके खिलाफ कोई शिकायत दायर नहीं किया था और केवल प्रतिवादी को आरोपी बनाया जिसने अधिवक्ता के रूप में कर रिटर्न प्रस्तुत किए। इसका मतलब यह है कि प्रतिवादी-आरोपी ने केवल आयकर रिटर्न जमा किया सभी दस्तावेजों के साथ मुख्य आँकलन करने वाले की ओर से। अन्य शब्दों में कहा जाए तो, सभी टीडीएस प्रमाण पत्र, जिन्हें उत्तरी रेल्वे द्वारा जारी किया गया था, मुख्य आँकलन करने वाले द्वारा अपने अधिवक्ता को आपूर्ति की गई थी। वह मुख्य आँकलन करने वाला था, जिन्होंने संबंधित अधिकारियों से दस्तावेजों की खरीद की थी और धनवापसी का दावा किया था। अगर मुख्य आँकलन करने वाले ने जाली टीडीएस प्रमाणपत्रों के आधार पर धनवापसी का दावा किया था, तब, आयकर प्राधिकरण आयकर अधिनियम के संबंधित प्रावधानों के तहत सक्षम थे और उनके धनवापसी के दावे को अस्वीकार करने का अधिकार क्षेत्र में थे। इसके बाद, पीड़ित पक्ष को अधिकार था इस प्रासंगिक कनेक्शन में वैधानिक अपील दर्ज करने का। इस में, जैसा कि हो सकता है, वैसा ही हो घटना, प्रतिवादी-आरोपी, जो एक वकील था, बस मुख्य आँकलन करने वाले की ओर से आयकर रिटर्न जमा करने आया था और इसी कारण संभवतः और वास्तव में अपराधिक अभियोजन के लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है मुख्य आँकलन करने वाले द्वारा दस्तावेजों की खरीद के लिए संकेतित अपराधों के दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करने के लिए, जैसा कि इसके विपरीत शिकायतकर्ता आईटीओ ने कहा है। इसी तरह, केवल तथ्य यह है कि उसने आँकलन करने वाले की ओर से आयकर रिटर्न तैयार किया था, वास्तव में, यह एक आधार नहीं है और इतना ठोस सबूत नहीं है कि प्रतिवादी-अभियुक्त को धारा 177 और 182 आईपीसी के तहत आँकलन करने वाल की अनुपस्थिति में दोषी करार करने के लिए।

- (15) इतना ही नहीं, इस मामले का एक और पहलू है, जिसे पूरी तरह से एक अलग कोण से देखा जा सकता है। रिकॉर्ड के अध्ययन से पता चलता है कि प्रतिवादी-अभियुक्त ने 24-11-1989 को आयकर रिटर्न जमा किया था और मुख्य आँकलन करने वाले ने रेलवे अधिकारियों से बहुत पहले टीडीएस प्रमाणपत्र प्राप्त किया था। प्रतिवादी अभियुक्त को मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया गया था, 3-7-1999 दिनांकित समन आदेश द्वारा और अंततः उसे धारा 177 और 182 आईपीसी के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए चरगेशीत किया गया था। संभवतः यहाँ विवादित नहीं हो सकता है संकेतित अपराधों के तहत निर्धारित अधिकतम सज़ा सरल है जिसकी कारावास की अवधि, जो प्रत्येक या छह महीने तक बढ़ सकता है या जुर्माना है, जो रु 1000 / - प्रत्येक या दोनों के साथ विस्तारित हो सकता है। क्रमानुसार, धारा 468 सी.आर.पी.सी. यह बताती है कि कोई भी न्यायालय अपराध का एक वर्ष की अवधि समाप्त होने के बाद संज्ञान नहीं लेगा जैसा की धारा 468 (1) (2) (बी) सी.आर.पी.सी.में लिखा है। धारा 468 सी.आर.पी.सी. का कार्यवाही की सीमा को रोकने के पीछे उद्देश्य यह है कि पार्टियाँ लंबे समय (देरी) के बाद मामले दर्ज करने ना आए और अपराध की तारीख के बाद लंबे समय के बाद झूठे और बेबुनियादि मामले दायर करके अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए। यह उद्देश्य जिसे कानून आगे बढ़ना चाहता है वह स्पष्ट रूप से अनुरूप है निष्पक्षता और त्वरित सुनवाई की अवधारणा से जो की भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 मे अवतरित है। इस प्रकार, यह अनिवार्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है कि कोई भी अभियोजन राज्य द्वारा या निजी शिकायतकर्ता द्वारा दायर किया गया हमेशा स्थापित कानून का पालन करने वाला होना चाहिए या फिर अभियोजन सीमा का

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

आधार पर विफल होने के जोखिम को उठाए। मेरे दिमाग के अनुसार, धारा 468 सी.आर.पी.सी. द्वारा लगाए अनिवार्य और वैधानिक बार को किसी भी परिस्थिति में और वास्तव में अनदेखा नहीं करना चाहिए। इस तरीके से, क्या बात करनी है मुख्य आँकलन करने वाले की अनुपस्थिति में, प्रतिवादी अभियुक्त को दोषी ठहराते हुए, यहां तक कि उसके खिलाफ पूरी आपराधिक कार्यवाही की शुरुआत कानून की नजर में गैर है। .

(16) इसलिए, अन्यथा भी, इंगित अपराधों का प्रतिवादी-अभियुक्त के खिलाफ संज्ञान लेना सीमा द्वारा भी रोक दिया गया था। इतना ही नहीं, प्रतिवादी-अभियुक्त, खिलाफ शिकायत की गैर-बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए, निहित कानूनी लाख के, लिंक साक्ष्य, विरोधाभास, असंभवता, समग्रता में कानून के रिकॉर्ड और कानून के बिंदु पर अनुपात को देखते हुए, ट्रायल कोर्ट ने उसको सही बरी कर दिया है, बरी करने का फैसला पदार्थ में, इस रूप में है: -

11.” यह बात यह साफ़ करती है कि क्या एक अधिवक्ता को उत्तरदायी ठहराया जा सकता है गलत/गलत आयकर रिटर्न जमा करने के लिए गैर-मौजूदा व्यक्तियों का नाम, जो कि अजीबोगरीब है धनवापसी के आकार में लाभ उठाने के लिए या यह लोक सेवक को नुकसान पहुंचाने का इरादा के साथ दायर किया गया था।

मैं इस तथ्य को इंगित करना चाहूंगा जो कि सबूतों के अनुसार शिकायतकर्ता लाए है। शुरू में काम करने वाले क्लर्क को रिटर्न दिया गया था जिसने उसे आगे आईटीओ को दिया, आइकर रिटर्न और अन्य दस्तावेजों के अध्ययन से पता चला, कि आईटीओ सक्षम था दावे को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए। यदि आईटीओ ने जाँच करने के बाद दावे को खारिज कर दिया तो आँकलन करने वाले व्यक्ति / को इस बात का नोटिस जारी करना आवश्यक थी कि क्या आँकलन करने वाले व्यक्ति / दावेदार ने रिटर्न जमा किया या नहीं लेकिन ऐसी कोई जांच नहीं हुई। दावेदार द्वारा इस न्यायालय के समक्ष आँकलन करने वाले व्यक्ति/ दावेदार के अस्तित्व का न होना जैसी किसी भी जांच को साबित नहीं किया गया। यह हालांकि स्पष्ट है कि यदि आईटीओ द्वारा किए दावे को स्वीकार किया जाना है तो धनवापसी राशि आँकलन करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा किया जाना चाहिए। इस तरह, एक वकील की कोई भूमिका नहीं थी फर्जी धनवापसी का दावा करने में क्योंकि यदि धनवापसी राशि जमा की जाती है आँकलन करने वाले के खाते में और अगर लोक सेवक के सामने कोई गलत दावा प्रस्तुत किया जाता है तो वह आसानी से अस्वीकार कर सकता है ऐसे दावे को। इसके अलावा, आईटीओ द्वारा नियमों के तहत आवश्यकतानुसार कार्यवाही शुरू की जानी चाहिए। वह एक वकील की पावर ऑफ अटॉर्नी लेने के लिए बाध्य था। साथ में रिटर्न पर सत्यापन या हलफनामा आँकलन करने वाले व्यक्ति के बारे में एक वकील द्वारा लेकिन ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं हो रही थी और ना ही इसे लागू किया गया व्यक्तिगत आँकलन करने वाले व्यक्ति खुद या अपने वकील या क्लर्क के माध्यम से।

यह आयकर रिटर्न आँकलन करने वाले / दावेदार के नाम पर है और इस पर किसी वकील के हस्ताक्षर नहीं है। मामले में, अगर अधिवक्ता ने इन रिटर्न को अपने स्वयं के लिखावट या आँकलन करने वाले की दिशा में भरा, तब भी कोई अपराध नहीं हुआ और अपराध का दायित्व एक वकील पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है जिसे निश्चित रूप से कोई धनवापसी प्राप्त नहीं, होगी बल्कि धनवापसी की यह राशि होनी चाहिए आँकलन करने वाले व्यक्ति के खाते में जमा किया गया। मामले में, यदि आँकलन करने वाले ने कुछ अस्पष्ट दस्तावेज एकत्र किए और आइकर रिटर्न के साथ संलग्न

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

कर दिए तो यह लोक सेवक का कर्तव्य है कि वह निष्पक्ष तरीके से प्रत्येक तथ्य की छानबीन करे, ताकि धनवापसी की स्वीकृति या अस्वीकृति का प्रश्न विवेकपूर्ण तरीके से निर्धारित किया जाए। इस रिटर्न का न तो किसी वकील द्वारा दी सत्यापन रिपोर्ट से न ही कोई हलफनामा से और ना हे किसी पावर ऑफ अटॉर्नी द्वारा समर्थित किया गया है और इस तरह से अगर कोई ऑकलन करने वाला नहीं मिला तो लोक सेवक आसानी से और विवेकपूर्ण तरीके से अपनी शक्ति का प्रयोग करके धनवापसी को अस्वीकार कर सकता है से। यहाँ आरोपी सुदेश शर्मा ने आईटीओ द्वारा पत्र जारी करने के लिए उत्तर और कारण में अपनी स्थिति बताई क्योंकि उन्होंने 11.6.1990 को आईटीओ के खिलाफ सिविल सूट की स्थापना की श्री इंदरजीत मेहता, उप न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, कुरुक्षेत्र की अदालत में, और नोटिस इस मामले में श्री एम.एल.जेन, तब आईटीओ को जारी किया गया और इस कारण श्री एम.एल.जेन, तब आईटीओ नाराज हो गए और आरोपी सुदेश शर्मा से बदला लेने के लिए इस शिकायत को शुरू किया।

12. अधिक से अधिक, वहाँ स्पष्ट रूप से साक्ष्य में लिंक गायब है जो मैं उजागर करना चाहता हूँ वह शिकायतकर्ता यह स्थापित करने में विफल रहा कि क्लर्क से पहले किसने रिटर्न जमा किया। यह नहीं स्थापित किया गया है कि एक वकील के क्लर्क, ऑकलन करने वाले / दावेदार या सुदेश शर्मा एडवोकेट ने क्लर्क से पहले रिटर्न जमा किया या सुसज्जित किया। शिकायतकर्ता उस क्लर्क की जांच करने में विफल रहा जिसने एक वकील द्वारा सत्यापन या हलफनामा के बिना आइकर रिटर्न प्राप्त किया। इस पृष्ठांकन के बारे में रिटर्न में कुछ भी उल्लेख नहीं किया गया है कि क्या रिटर्न में उल्लेखित सामग्री सच है मेरे ज्ञान को मद्देनजर रखते हुए सही है और ना ऑकलन करने वाले का और न ही किसी वकील के उस पर हस्ताक्षर है। यह रिटर्न किसी भी पावर ऑफ अटॉर्नी के साथ समर्थित नहीं है, इसलिए यह आसानी से कहा जा सकता है कि यह किसी भी ऑकलन करने वाले के प्राधिकरण द्वारा साबित नहीं हुआ है जिसकी ओर से दावा / धनपवसी की मांग की गई थी रिटर्न के जमा करने के समय पर। कि एक आयकर अधिकारी और एक इंस्पेक्टर नियुक्त किया गया है जो एक वर्ष में 4000-5000 से अधिक रिटर्न पर काम करते थे, यदि ऐसा था तो अधिवक्ता को पत्र जारी करने से पहले, आईटीओ को किसी अधिवक्ता का पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त करना चाहिए था ऑकलन करने वाले / दावेदार से संबंधित और रिटर्न में उल्लेख किया गया सामग्री के संबंध में हलफनामा और सत्यापन रिपोर्ट जो यह बताए की रिटर्न में लिखे शब्द सही है और वास्तविक रूप से असली है। लेकिन ऐसा कोई हलफनामा या सत्यापन नहीं माँगा गया रिटर्न के साथ। रिपोर्ट प्रस्तुत करने के समय, आईटीओ फ्रेम कर सकता है या ऑकलन करने वाले के पैन कार्ड या ऑकलन करने वाले की किसी अन्य पहचान को प्रस्तुत करने के लिए एक वकील को निर्देशित करें ताकि दावा का विवेकपूर्ण तरीके से निर्णय लिया जाए। हालाँकि, फ़ाइल पर रिकॉर्ड के अनुसार ऑकलन करने वाले से ऐसा कोई पहचान को प्राप्त नहीं किया गया है। चूंकि, दावे / धनपवसी को ऑकलन करने वाले के खाते में जमा किया जाना था तब यह नहीं कहा जा सकता है कि एक वकील नकली टीडीएस प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा नियोक्ता से कोई धन-संबंधी लाभ शिकायतकर्ता विभाग से लेने के लिए।

यदि कोई नियोक्ता / ठेकेदार / रेलवे विभाग कोई धन-संबंधी लाभ किसी नकली ऑकलन करने वाले का बैंक खाता खोलने के माध्यम से उठाते है। तब लाभ नियोक्ता या ठेकेदार या विभाग द्वारा प्राप्त किया जाना चाहिए इस तरह यह एक वकील की किसी भी तरह कोई भूमिका को विशेषता नहीं देगा शिकायतकर्ता विभाग से लाभ प्राप्त करने में। हालाँकि आईटीओ ने ठेकेदार / नियोक्ता / विभाग के बारे में कोई पूछताछ ना की ना ही यह माना जा सकता है कि यह एक वकील की कार्रवाई थी गलत रिटर्न

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

प्रस्तुत करके पैसे के आकार में अनुचित लाभ उठाने की क्योंकि यह आयकर विभाग के अधिकार में है या तो दावे को स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है जैसा कि नियम के अनुसार मांग की गई है। इस मामले में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा रिटर्न के साथ संलग्न दस्तावेजों की उचित जांच के बाद दावा/धनपवसी को सही तरीके से खारिज कर दिया गया है।

उस शिकायतकर्ता विभाग ने न तो कोई नोटिस जारी किया नियोक्ता/ ठेकेदार/विभाग और न ही कोई जांच की रिपोर्ट प्रस्तुत करी। मामले में, सुदेश शर्मा ने अपेक्षित प्रदर्शन आदि अपने हाथ से लिखने में भरे तब भी यह नहीं कहा जा सकता है कि अधिवक्ता ने रिटर्न प्रस्तुत कोई लाभ उठाने के लिए किए क्योंकि धनपावसी/दावे को ऑकलन करने वाले के खाते में जमा किया जाना था।

तक अन्यथा, यह एक वकील का कर्तव्य है कि वह ऑकलन करने वाले की ओर से आयकर प्राधिकरण के समक्ष दावा करे और यदि उचित जांच के बाद प्राधिकरण ने इसे उचित या गलत नहीं पाया तब दावा आसानी से खारिज किया जा सकता है। तो, यह नहीं समझने योग्य है की विशेषज्ञ रिपोर्ट को प्राप्त करने की आवश्यकता क्यों थी रिटर्न में उल्लिखित लेखन की तुलना करने के लिए क्योंकि धनवापसी की राशि वकील का खाता में नहीं जानी थी। इसलिए, उन्हें इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया गया ऑकलन करने वाले की ओर से गलत जानकारी प्रस्तुत करने के लिए क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अस्तित्व में नहीं है तब भी धनवापसी / दावा यदि स्वीकार किया गया तब उनके खाते में जमा नहीं किया जा सकता है। इस मामले में, सुदेश शर्मा द्वारा पत्र का विधिवत उत्तर दिया गया था लेकिन तब भी अनावश्यक साक्ष्य एकत्र किए जा रहे थे वकील पर अनुचित बोझ को स्थानांतरित करने के लिए जिसकी कोई भूमिका नहीं थी लाभ प्राप्त करने में ऑकलन करने वाले की ओर से रिटर्न जमा करते समय।

उस आईटीओ ने इंसपेक्टर को भेजते समय ऑकलन करने वाले के बारे में सत्यापित किया व्यक्तिगत रूप से और निरीक्षक की रिपोर्ट प्राप्त होने पर ऑकलन करने वाले के अस्तित्व के बारे में, ऑकलन करने वाले से संबंधित दावा खारिज कर दिया गया था लेकिन यह किसी वकील को ऑकलन करने वाले की ओर से गलत आयकर रिटर्न जमा करने के लिए अपराधी नहीं बनाएगा

- (17) इसका मतलब है कि ट्रायल कोर्ट ने मामले की जांच की है सही परिप्रेक्ष्य और प्रतिवादी-अभियुक्त को सही ढंग से बरी कर दिया। याचिकाकर्ताओं के वकील ने किसी भी दस्तावेज़ को इंगित नहीं किया था ना कोई ठोस सबूत दिया बरी करने का निर्णय में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने के लिए। इस तरह के वैध कारणों के साथ व्यक्त किए गए बारी करने के निर्णयों में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है इस न्यायालय द्वारा धारा 378 (4) Cr.PC के तहत सीमित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करके, जब तक की यह समान अवैध, विकृत और अधिकार क्षेत्र के बिना नहीं है। चूंकि ऐसी कोई समान अवैधता या कानूनी दुर्बलता नहीं बताई गई है याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा, इसलिए, बरी होने के निर्णय को बनाए रखा गया है यहाँ-ऊपर उल्लेख किया गए कारणों के कारण।
- (18) मामले की कोई और कानूनी परिस्थिति जो विचार के लायक हो, याचिकाकर्ता के वकील द्वारा ना तो आग्रह किया ना दबाया गया।
- (19) पूर्वोक्त कारणों के आलोक में, क्योंकि कोई योग्यता नहीं है, इसलिए, अपील करने के लिए छुट्टी की तत्काल याचिकाएं खारिज कर दी जाती हैं।

आइकर अधिकारी और अन्य बनाम सुदेश शर्मा
(मेहिंदर सिंह सुलार, न्यायाधीश)

जे.एस. मेहंदीराता

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

अरुणिमा चौहान

प्रशिक्षु न्यशियक अधिकारी

(Trainee Judicial Officer)

पंचकुला, हरियाणा